

Q No 03 साख नियंत्रण की मात्रात्मक (Quantitative) एवं गुणात्मक (Qualitative) विधियाँ

(Explain the Quantitative and Qualitative Methods of Credit Control)

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग प्रणाली का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बैंक जनता से जमा स्वीकार करते हैं तथा उद्योग, व्यापार, कृषि और सेवा क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराते हैं। यदि बैंकों द्वारा अत्यधिक ऋण दिया जाए तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मुद्रास्फीति (Inflation) उत्पन्न हो सकती है। दूसरी ओर यदि ऋण की उपलब्धता बहुत कम हो जाए तो निवेश, उत्पादन तथा रोजगार में कमी आ जाती है और अपस्फीति (Deflation) की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अर्थव्यवस्था में साख (Credit) की मात्रा तथा उसके उपयोग को नियंत्रित करना आवश्यक होता है।

यह कार्य देश का केंद्रीय बैंक करता है। भारत में यह जिम्मेदारी Reserve Bank of India (RBI) निभाता है। RBI समय-समय पर विभिन्न मौद्रिक नीतियों (Monetary Policies) के माध्यम से बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को नियंत्रित करता है। इस प्रक्रिया को साख नियंत्रण (Credit Control) कहा जाता है।

साख नियंत्रण का उद्देश्य केवल ऋण की मात्रा को कम या अधिक करना ही नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि ऋण सही क्षेत्रों में जाए और उसका उपयोग उत्पादक कार्यों में हो। साख नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक दो प्रकार की विधियों का उपयोग करता है—

- मात्रात्मक या सामान्य साख नियंत्रण की विधियाँ (Quantitative or General Methods)
- गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण की विधियाँ (Qualitative or Selective Methods)

साख नियंत्रण का अर्थ (Meaning of Credit Control)

साख नियंत्रण से आशय उन उपायों से है जिनके द्वारा केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में उपलब्ध ऋण की मात्रा तथा उसके उपयोग की दिशा को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य मुद्रा की आपूर्ति को संतुलित रखना, मूल्य स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाना है।

साख नियंत्रण के उद्देश्य (Objectives of Credit Control)

- मूल्य स्थिरता बनाए रखना।
- मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति पर नियंत्रण करना।
- आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- पूर्ण रोजगार प्राप्त करने में सहायता करना।
- बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त तरलता बनाए रखना।
- उत्पादन एवं निवेश को प्रोत्साहित करना।
- विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन बनाए रखना।
- आवश्यक क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग एवं लघु उद्यमों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना।
- सट्टेबाजी तथा अनुत्पादक ऋणों पर नियंत्रण करना।

साख नियंत्रण की मात्रात्मक (Quantitative) विधियाँ

मात्रात्मक विधियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कुल साख (Total Credit) की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। इनका प्रभाव सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली पर पड़ता है।

1. बैंक दर नीति (Bank Rate Policy)

बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है।

कार्यप्रणाली

- यदि RBI बैंक दर बढ़ा देता है—
- बैंकों के लिए ऋण लेना महंगा हो जाता है।
- बैंक जनता को कम ऋण देते हैं।

- बाजार में मुद्रा की मात्रा घटती है।
- मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है।
- यदि बैंक दर घटाई जाती है—
- ऋण सस्ता हो जाता है।
- निवेश एवं उत्पादन बढ़ते हैं।
- रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।

लाभ

- मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है।
- निवेश को प्रभावित करता है।
- आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में सहायक है।

2. खुला बाजार परिचालन (Open Market Operations - OMO)

- इस विधि में RBI सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करता है।
- प्रतिभूतियों की बिक्री
- बाजार से नकदी वापस RBI के पास चली जाती है।
- बैंकों की ऋण देने की क्षमता कम हो जाती है।
- साख का संकुचन होता है।
- प्रतिभूतियों की खरीद
- बाजार में नकदी बढ़ जाती है।
- बैंक अधिक ऋण देते हैं।
- निवेश एवं उत्पादन बढ़ते हैं।

महत्व

यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का प्रभावी साधन है।

बैंकिंग प्रणाली में तरलता बनाए रखता है।

3. नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio - CRR)

प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास नकद के रूप में रखना पड़ता है।

प्रभाव

CRR बढ़ाने पर बैंक कम ऋण दे पाते हैं।

CRR घटाने पर बैंक अधिक ऋण देने लगते हैं।

महत्व

मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है।

बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षित बनाता है।

4. वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio - SLR)

SLR वह प्रतिशत है जिसे बैंक अपनी जमा राशि का एक भाग नकद, सोना अथवा सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखते हैं।

प्रभाव

SLR बढ़ाने पर ऋण देने की क्षमता घटती है।

SLR घटाने पर ऋण देने की क्षमता बढ़ती है।

5. रेपो दर (Repo Rate)

रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है।

प्रभाव

रेपो दर बढ़ने पर ऋण महँगा होता है।

रेपो दर घटने पर ऋण सस्ता हो जाता है।

6. रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate)

यह वह दर है जिस पर RBI बैंकों से अतिरिक्त धन स्वीकार करता है।

प्रभाव

रिवर्स रेपो दर बढ़ने पर बैंक अपना अतिरिक्त धन RBI के पास जमा करते हैं।

बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है।

7. परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात (Variable Reserve Ratio)

केंद्रीय बैंक समय-समय पर आरक्षित अनुपात में परिवर्तन करके बैंकों की ऋण देने की क्षमता को नियंत्रित करता है।

मात्रात्मक विधियों के लाभ

मुद्रास्फीति पर नियंत्रण।

अपस्फीति से बचाव।

बैंकिंग प्रणाली में संतुलन।

आर्थिक विकास को गति।

निवेश एवं उत्पादन को प्रभावित करना।

मुद्रा आपूर्ति का प्रभावी नियंत्रण।

साख नियंत्रण की गुणात्मक (Qualitative) विधियाँ

गुणात्मक विधियों का उद्देश्य कुल साख को नियंत्रित करना नहीं बल्कि साख की दिशा (Direction of Credit) को नियंत्रित करना होता है। इनका प्रयोग विशेष क्षेत्रों के लिए किया जाता है।

1. नैतिक समझाइश (Moral Suasion)

RBI बैंकों को सलाह, निर्देश एवं अनुरोध देकर उचित क्षेत्रों में ऋण देने के लिए प्रेरित करता है।

महत्व

यह एक सरल एवं प्रभावी उपाय है।

इसमें कानूनी दंड की आवश्यकता नहीं होती।

2. प्रत्यक्ष कार्रवाई (Direct Action)

यदि कोई बैंक RBI के निर्देशों का पालन नहीं करता तो RBI उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है।

उदाहरण

पुनर्वित्त सुविधा रोकना।

जुर्माना लगाना।

लाइसेंस संबंधी कार्रवाई करना।

3. ऋण राशनिंग (Credit Rationing)

RBI यह निर्धारित करता है कि बैंक अधिकतम कितनी राशि तक ऋण दे सकते हैं।

उद्देश्य

अत्यधिक ऋण वितरण रोकना।

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराना।

4. मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन (Variation in Margin Requirement)

मार्जिन वह अंतर है जो प्रतिभूति के बाजार मूल्य और उसके विरुद्ध दिए गए ऋण के बीच होता है।

मार्जिन बढ़ाने पर ऋण कम मिलता है।

मार्जिन घटाने पर ऋण अधिक मिलता है।

5. उपभोक्ता साख का विनियमन (Regulation of Consumer Credit)

उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए दिए जाने वाले ऋण की शर्तों को नियंत्रित किया जाता है।

उदाहरण

डाउन पेमेंट बढ़ाना।

किश्तों की संख्या कम करना।

ऋण अवधि सीमित करना।

6. प्रचार एवं जनजागरण (Publicity)

RBI अपनी वार्षिक रिपोर्ट, मौद्रिक नीति, प्रेस विज्ञप्ति तथा दिशानिर्देशों के माध्यम से जनता और बैंकों को जानकारी प्रदान करता है।

7. प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending)

RBI बैंकों को कृषि, लघु उद्योग, शिक्षा, आवास तथा कमजोर वर्गों को निर्धारित अनुपात में ऋण देने के निर्देश देता है।

गुणात्मक विधियों के लाभ

- ऋण का सही दिशा में उपयोग सुनिश्चित होता है।
- कृषि एवं लघु उद्योगों को सहायता मिलती है।
- सट्टेबाजी पर नियंत्रण होता है।
- आवश्यक क्षेत्रों का विकास होता है।
- संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
- मात्रात्मक एवं गुणात्मक विधियों में अंतर
- आधार

- मात्रात्मक विधियाँ
- गुणात्मक विधियाँ

उद्देश्य

कुल साख की मात्रा नियंत्रित करना

साख की दिशा नियंत्रित करना

प्रभाव

सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली पर

विशेष क्षेत्रों पर

प्रकृति

सामान्य नियंत्रण

चयनात्मक नियंत्रण

उदाहरण

- बैंक दर, CRR, SLR, OMO, रेपो दर
- नैतिक समझाइश, ऋण राशनिंग, मार्जिन, प्रत्यक्ष कार्रवाई
- साख नियंत्रण का महत्व (Importance of Credit Control)
- मूल्य स्थिरता बनाए रखता है।
- आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है।
- मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति को नियंत्रित करता है।
- बैंकिंग प्रणाली में संतुलन बनाए रखता है।
- निवेश एवं उत्पादन को बढ़ावा देता है।
- रोजगार सृजन में सहायता करता है।
- वित्तीय प्रणाली को स्थिर बनाता है।
- विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन में सहायता करता है।

सीमाएँ (Limitations)

- मात्रात्मक विधियाँ सभी क्षेत्रों को समान रूप से प्रभावित करती हैं।
- गुणात्मक विधियों की सफलता बैंकों के सहयोग पर निर्भर करती है।
- अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों पर इनका प्रभाव सीमित रहता है।
- विकासशील देशों में इनकी प्रभावशीलता अपेक्षाकृत कम हो सकती है।
- अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप से बैंकिंग कार्य प्रभावित हो सकते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

साख नियंत्रण किसी भी केंद्रीय बैंक का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मात्रात्मक विधियाँ अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा एवं ऋण की मात्रा को नियंत्रित करती हैं, जबकि गुणात्मक विधियाँ यह सुनिश्चित करती हैं कि ऋण का प्रवाह सही और उत्पादक क्षेत्रों की ओर हो। दोनों प्रकार की विधियाँ एक-दूसरे की पूरक हैं और मिलकर मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास, रोजगार वृद्धि, वित्तीय अनुशासन तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देती हैं। वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिवेश में, जहाँ मुद्रास्फीति, वित्तीय अस्थिरता और बदलती बाजार परिस्थितियाँ निरंतर चुनौती बनी हुई हैं, वहाँ केंद्रीय बैंक द्वारा इन दोनों प्रकार की साख नियंत्रण विधियों का संतुलित एवं प्रभावी उपयोग किसी भी देश की आर्थिक प्रगति और वित्तीय स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है।